

21वीं सदी में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

रंजू सिंह

<https://doi.org/10.61410/had.v31i3.338>

शोध सार

इक्कीसवीं सदी में विज्ञान प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण तथा डिजिटल परिवर्तन और रोजगार के बदलते स्वरूप ने शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्यों को व्यापक रूप में प्रभावित किया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल पुस्तक ज्ञान और परीक्षा केन्द्रित शिक्षा पर्याप्त नहीं रह गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का तुलनात्मक विवेचन करते हुए 21वीं सदी के आवश्यकताओं के सन्दर्भ में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। यह लेख रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्ता पूर्ण और रोजगार परक बनाते हुए विद्यार्थियों में अधिक रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान तथा आत्मनिर्भरता का विकास करना है।

मुख्य शब्द — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वैश्वीकरण, समावेशी शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, रोजगार परक, आलोचनात्मक चिंतन, आत्मनिर्भरता।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। किसी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित, जागरूक और कुशल नागरिकों पर निर्भर करती है। अच्छी शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्ति में सही सोच, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, नवाचार तथा जिम्मेदारी की भावना का भी विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। समय के साथ समाज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा लोगों की आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हुआ है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में भी समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक हो गया।

ज्ञानं विज्ञानसंयुक्तं कौशलैः समलङ्कृतम्।

एतदेव हि शिक्षायाः लक्ष्यं भवति शाश्वतम्॥

अर्थः ज्ञान, विज्ञान और कौशल से युक्त शिक्षा ही शिक्षा का शाश्वत एवं आदर्श लक्ष्य है।

भारत में वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। उस समय यह नीति देश की आवश्यकताओं के अनुरूप थी, किंतु बदलते वैश्विक परिवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास, रोजगार की नई आवश्यकताओं तथा कौशल-आधारित शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अनुभव की गई। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-2020) लागू की। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी,

- असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय, धामपुर, बिजनौर

लचीला, गुणवत्तापूर्ण तथा रोजगारोन्मुख बनाना है। इसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, कौशल-विकास, मातृभाषा में शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अनुसंधान तथा नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है, जो ज्ञानवान, आत्मनिर्भर, जिम्मेदार, नैतिक मूल्यों से युक्त तथा भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हों और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

पुरानी शिक्षा नीति (1986) का उद्देश्य एवं विशेषताएँ

पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, निरक्षरता को कम करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना था। इस नीति के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि सभी बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर मिले और शिक्षा का लाभ ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों तक भी पहुँचे। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति के अंतर्गत पूरे देश में 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। इसके अनुसार विद्यार्थी 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 2 वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करते थे। यह व्यवस्था लंबे समय तक भारत की शिक्षा प्रणाली का आधार बनी रही। पुरानी शिक्षा नीति में पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना माना जाता था। शिक्षण प्रक्रिया अधिकतर रटने (Rote Learning) पर आधारित थी। विद्यार्थियों से विषयों को समझने, प्रयोग करने या उन पर विचार करने की अपेक्षा उन्हें याद करके परीक्षा में लिखने पर अधिक जोर दिया जाता था। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक सोच, समस्या-समाधान क्षमता तथा व्यावहारिक ज्ञान का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता था।

इस नीति में माध्यमिक स्तर के बाद विद्यार्थियों को मुख्यतः विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी अलग-अलग धाराओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता था। एक धारा चुन लेने के बाद दूसरी धारा के विषयों को पढ़ने की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। उदाहरण के लिए, विज्ञान का विद्यार्थी संगीत, चित्रकला या अर्थशास्त्र जैसे विषय आसानी से नहीं पढ़ सकता था। इससे विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता कम हो जाती थी। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता था। परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर पाते थे, जबकि रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता था। शिक्षा और रोजगार के बीच भी अपेक्षित समन्वय का अभाव था। यद्यपि अपने समय की परिस्थितियों में यह नीति प्रभावी और उपयोगी सिद्ध हुई तथा देश में शिक्षा के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, किंतु बदलते समय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास, वैश्वीकरण, डिजिटल युग तथा कौशल-आधारित शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई। यही आवश्यकता आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण का आधार बनी।

नई शिक्षा नीति (2020) की विशेषताएँ

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि आज की शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न होकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार बने।

वर्तमान समय में विज्ञान, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डिजिटल शिक्षा, वैश्वीकरण और रोजगार के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों में समस्या-समाधान की क्षमता, रचनात्मक सोच, संचार कौशल, तकनीकी दक्षता तथा व्यावहारिक ज्ञान का विकास भी आवश्यक है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीख सके। यह नीति विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने पर बल देती है। इसमें शिक्षा को अधिक सरल, लचीला, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख तथा कौशल-आधारित बनाने का प्रयास किया गया है। इस नीति के अंतर्गत **10+2** शिक्षा प्रणाली के स्थान पर **5+3+3+4** शिक्षा संरचना लागू की गई है। यह व्यवस्था **3** से **18** वर्ष तक के बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अंतर्गत **3** से **8** वर्ष तक की आयु को आधारभूत (Foundational Stage), **8** से **11** वर्ष तक को प्रारंभिक (Preparatory Stage), **11** से **14** वर्ष तक को मध्य (Middle Stage) तथा **14** से **18** वर्ष तक को माध्यमिक (Secondary Stage) के रूप में विभाजित किया गया है। इससे बच्चों की आयु और सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। नई शिक्षा नीति में रटकर याद करने की पुरानी पद्धति को कम महत्व दिया गया है। इसके स्थान पर समझने, सोचने, प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने, प्रयोग करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। अब विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, कौशल, व्यवहार, रचनात्मकता और समग्र विकास के आधार पर भी किया जाएगा।

इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है। अब विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी धाराओं की कठोर सीमाएँ पहले की तरह नहीं रहेंगी। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी विज्ञान के साथ संगीत, चित्रकला, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र या अन्य विषय भी पढ़ सकता है। इससे उनकी प्रतिभा का बेहतर विकास होगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर भी विशेष बल दिया गया है। नीति के अनुसार कम से कम कक्षा **5** तक और जहाँ संभव हो, कक्षा **8** तक बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इससे बच्चे विषयों को अधिक आसानी से समझ सकेंगे तथा उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस नीति में कक्षा **6** से ही व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था से ही विभिन्न व्यवसायों और कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को भी विशेष महत्व दिया गया है। इससे विद्यार्थी बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे और नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग करना सीखेंगे। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षा में आधुनिक संसाधनों के उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समान अवसरों वाली बनाना है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों, दिव्यांग विद्यार्थियों तथा वंचित समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल शिक्षित नागरिक तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे आत्मनिर्भर, कुशल, नवाचारी, नैतिक, जिम्मेदार और वैश्विक दृष्टिकोण वाले नागरिकों का निर्माण करना है, जो अपने व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। पुरानी शिक्षा नीति और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे बड़ा अंतर शिक्षा की संरचना में है। पुरानी शिक्षा नीति में 10+2 प्रणाली लागू थी, जबकि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 प्रणाली अपनाई गई है। यह नई व्यवस्था 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शिक्षण पद्धति में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को रटकर पढ़ने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके विपरीत नई शिक्षा नीति में विषयों को समझने, अनुभव के माध्यम से सीखने, गतिविधियों में भाग लेने, प्रश्न पूछने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना है। विषयों के चयन में भी नई शिक्षा नीति ने अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। पहले विद्यार्थियों को विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी अलग-अलग धाराओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता था। एक बार धारा चुनने के बाद दूसरे विषयों को पढ़ने की सुविधा बहुत कम होती थी। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी विज्ञान के साथ संगीत या चित्रकला जैसे विषय भी पढ़ सकता है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पुरानी शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। नई शिक्षा नीति में इस आयु वर्ग की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना गया है, ताकि बच्चों का बौद्धिक और भावनात्मक विकास प्रारंभ से ही सही दिशा में हो सके। भाषा के क्षेत्र में भी नई नीति अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसमें कक्षा 5 तक तथा जहाँ संभव हो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे बच्चे विषयों को आसानी से समझ पाते हैं और उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। पुरानी शिक्षा नीति में इस विषय पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया था। मूल्यांकन प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है। पहले विद्यार्थियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से वार्षिक परीक्षा और प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। नई शिक्षा नीति में सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परियोजना कार्य, व्यावहारिक कार्य तथा कौशल-आधारित आकलन को महत्व दिया गया है। इससे विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। इसमें कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, इंटरनशिप, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास को शामिल किया गया है। साथ ही डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके विपरीत पुरानी शिक्षा नीति में इन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया था।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नीति अधिक लचीली है। इसमें बहु-प्रवेश (Multiple Entry), बहु-निकास (Multiple Exit) तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली (Academic Bank of Credits) जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। इससे यदि किसी विद्यार्थी को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो वह बाद में उसी स्तर से अपनी शिक्षा पुनः शुरू कर सकता है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लाभ :-

1. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों का केवल शैक्षिक विकास करना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ खेल, कला, संगीत, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा जीवन मूल्यों को भी महत्व दिया गया है, जिससे विद्यार्थी एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

2. रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास

नई शिक्षा नीति में रटकर पढ़ने की पुरानी पद्धति को कम महत्व दिया गया है। इसके स्थान पर विद्यार्थियों को विषयों को समझने, प्रश्न पूछने, तर्क करने, नए विचार प्रस्तुत करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे उनकी रचनात्मकता, तार्किक क्षमता और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। यह उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है।

3. कौशल एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा

नई शिक्षा नीति में केवल डिग्री प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल विकास को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इससे विद्यार्थी प्रारंभ से ही विभिन्न कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं और भविष्य में रोजगार या स्वरोजगार के लिए अधिक सक्षम बनते हैं।

4. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा का विस्तार

वर्तमान समय डिजिटल युग का है। इसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल सामग्री तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे विद्यार्थी नई तकनीकों से परिचित होते हैं और बदलती दुनिया के अनुसार स्वयं को तैयार कर पाते हैं। साथ ही, शिक्षा को अधिक प्रभावी, सरल और सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

5. विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता

नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। अब विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसी धाराओं की

कठोर सीमाएँ पहले जैसी नहीं हैं। विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकते हैं। इससे वे अपनी प्रतिभा का बेहतर विकास कर सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार करियर बना सकते हैं।

6. शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक बनाना

नई शिक्षा नीति में शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें प्रयोग, परियोजना कार्य, समूह चर्चा, अनुभवात्मक शिक्षण, इंटरनशिप और वास्तविक जीवन से जुड़े कार्यों को महत्व दिया गया है। इससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और जीवन तथा रोजगार दोनों के लिए अधिक तैयार करती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफल बनाने के लिए केवल नई योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन भी आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों और नई शिक्षण पद्धतियों का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब शिक्षक नई व्यवस्था को अच्छी तरह समझेंगे, तभी वे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सकेंगे। विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता भी बहुत आवश्यक है। सभी विद्यालयों में अच्छी इमारतें, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, आधुनिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाएँ और अन्य डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था भी आवश्यक है, ताकि सभी विद्यार्थी आधुनिक तकनीक का लाभ प्राप्त कर सकें। नई शिक्षा नीति का लाभ तभी सभी तक पहुँचेगा, जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। आज भी अनेक ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों, भवनों और तकनीकी सुविधाओं की कमी है। इसलिए सरकार को इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा, ताकि किसी भी विद्यार्थी को केवल स्थान या आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।

इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा विभाग, विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाजकृसभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नीति के उद्देश्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे। इसके साथ ही समय-समय पर नीति की प्रगति की समीक्षा करना, आवश्यक सुधार करना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना भी आवश्यक है। यदि सभी संबंधित पक्ष मिलकर ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, समावेशी और रोजगारोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा भारत को ज्ञान-आधारित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

उपसंहार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराना या डिग्री दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन में सफल होने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने समय में शिक्षा के प्रसार, साक्षरता बढ़ाने तथा देश के विभिन्न वर्गों तक शिक्षा पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। किंतु समय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा, रोजगार के बदलते स्वरूप तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देती है। इसमें रटने की अपेक्षा समझने, सोचने, कौशल विकसित करने, नई तकनीकों का उपयोग करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। साथ ही, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा दिया गया है। इससे विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे।

हालाँकि, इस नीति की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक विद्यालय, पर्याप्त संसाधन, डिजिटल सुविधाएँ तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों, शिक्षकों, विद्यालयों, अभिभावकों और समाजकृसभी को मिलकर इस नीति को सफल बनाने के लिए सहयोग करना होगा। यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी ईमानदारी, प्रभावी योजना और सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगी, बल्कि ऐसे जागरूक, कुशल, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक तैयार करेगी, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस प्रकार यह नीति भारत को ज्ञान-आधारित, आत्मनिर्भर, विकसित और विश्व स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography):

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)। नई दिल्ली, भारत सरकार, 2020।
<https://www-education-gov-in>
2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education, 1986)। नई दिल्ली, भारत सरकार, 1986।
<https://www-education-gov-in>
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curriculum Framework)। नई दिल्ली, भारत सरकार, 2005।
<https://www-ncert-nic-in>
4. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा—विद्यालयी शिक्षा (National Curriculum Framework for School Education)। नई दिल्ली, भारत सरकार, 2023।
<https://www-education-gov-in>

- 5- University Grants Commission (UGC)- National Education Policy 2020: Higher Education and Academic Reforms- New Delhi: University Grants Commission] 2020A
<https://www-ugc-gov-in>
- 6- University Grants Commission (UGC)- Academic Bank of Credits: Guidelines and Regulations- New Delhi: University Grants Commission, 2021A
<https://www-ugc-gov-in>
- 7- University Grants Commission ¼UGC½- Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes- New Delhi: UGC] 2022A
<https://www-ugc-gov-in>
- 8- National Council of Educational Research and Training ¼NCERT½- National Education Policy 2020: Transforming Education in India- New Delhi: NCERT] 2020A
<https://www-ncert-nic-in>
- 9- National Council of Educational Research and Training (NCERT)- National Curriculum Framework for Foundational Stage- New Delhi: NCERT, 2022A
<https://www-ncert-nic-in>
10. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित दस्तावेज एवं दिशा-निर्देश। नई दिल्ली, भारत सरकार, 2020–2025A
<https://www-education-gov-in>
11. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report)। नई दिल्ली, भारत सरकार, 2023–24A
<https://www-education-gov-in>
- 12- Ministry of Education] Government of India- All India Survey on Higher Education (AISHE) Final Report 2021–22- New Delhi: Government of India, 2024A
<https://aishe-gov-in>
- 13- Ministry of Education, Government of India- Performance Grading India for Districts (PGI&D)A New Delhi: Government of India, 2023–24A
<https://www-education-gov-in>
- 14- University Grants Commission- Guidelines on Examinations and Academic Calendar in the Context of Higher Education Reforms- New Delhi: UGC, 2020A
<https://www-ugc-gov-in>
- 15- National Statistical Office (NSO)- Household Social Consumption on Education in India- New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India, 2019A
<https://www-mospi-gov-in>
- 16- NCERT- Educational Statistics at a Glance- New Delhi: National Council of Educational Research and Training, 2018A
<https://www-ncert-nic-in>
- 17- Ministry of Education] Government of India- National Achievement Survey (NAS) 2021 Report- New Delhi: Government of India, 2022A
<https://www-education-gov-in>

ID: Email ranjusinghrajput90@gmail.com
